MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Dismal performance of Government in creating job opportunities in organized and unorganized sectors

श्री शरद यादव (बिहार)ः श्रीमन्, मैं एक गंभीर सवाल को यहां उठा रहा हूं। परसों पूना में नौ मज़दूर, जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर थे, एक बिल्डिंग के गिरने से उनकी जान चली गई। मैंने आज रूल 267 में आपको नोटिस दिया था। देश में एक करोड़ बीस लाख लोग हर वर्ष बेकार और बेरोजगार हो रहे हैं, यह आपका श्रम मंत्रालय कहता है। पहले जहां पांच-छह करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था, अब वहां सिर्फ एक करोड़ 30 लाख लोगों के पास रोजगार है। हर वर्ष एक करोड़ बीस लाख... इस देश में ऐसे हालात हैं कि जो लेबर लॉज़ हैं, उन लेबर लॉज़ में बदलाव नहीं किया है। हमने उनको इस तरह से बदला है कि एक कांट्रेक्ट लेबर का रोग पूरे देश में पूरी तरह से फैला हुआ है। कांट्रेक्ट लेबर का मतलब है कि जो लेबर लॉज़ हैं, उसको उससे बाहर निकाल दो। इसका मतलब है कि हिन्दुस्तान के जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो 80 फीसदी लोग हैं, जिनको एक विशेष अवसर के सिद्धान्त के तहत हिस्सा मिलता है, वह नहीं मिलेगा। मैं एक और बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आप लेबर लॉज़ को नहीं बदल सके, लेकिन हमारा देश ऐसा अद्‌भुत है कि हमने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया। अगर कोई प्राइवेट निकालता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यह रास्ता सरकार ने निकाला है। यह सदन जो यहां पर बैठा हुआ है, आप इस सदन के मालिक हैं, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा कांट्रेक्ट लेबर लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी कांट्रेक्ट लेबर के हैं, पानी देने वाले लोग कांट्रेक्ट लेबर के हैं। कांट्रेक्ट लेबर रखने का मतलब है कि किसी तरह की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हिन्दुस्तान के कानून में सैंकड़ों वर्ष की लड़ाई के बाद मजदूरों ने जो हासिल किया है, उसको बाई पास करना, उसको अलग करना है और यह बात charity begins at home. यहीं से हम लोग, इसी सदन से, इसी सदन में हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, यहां पर कांट्रेक्ट लेबर भरा हुआ है, चारों तरफ भरे हुए हैं। सरकार की तरफ से ऐसा काम होता है, तो अफसोस होता है, हमें तकलीफ होती है। आपको कानून का पालन करना चाहिए। वह आप कर नहीं रहे हैं। आज तो पूरे देश में, सारे जो उद्योगपति हैं, ये उद्योगपति 8 फीसदी रोजगार देते हैं। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्यः यह कांस्टीट्यूशन का वॉयलेशन है। ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादवः मेरी आपसे विनती है, मेरा सरकार से कहना है कि यह मामूली मामला नहीं है। हिन्दुस्तान में काफी बेकारी और बेरोजगारी है। जो कांवड़िए हैं, ये सब के सब बेकार और बेरोजगार हैं। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापतिः हो गया।

श्री शरद यादवः यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे नोटिस को आप accept करें। यह कांट्रेक्ट लेबर का काम खत्म होना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री शमशेर सिंह डुलो (पंजाब)ः उपसभापति महोदय, लेबर लॉज़ का वायलेशन हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... यहां बंद करने की कोशिश की जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): सर, यह बात सदन में पहले भी उठाई गई थी। ...**(व्यवधान)**... हमने मांग की थी कि देश में रोजगार कम हो रहा है, लेकिन उस दिन इस बात पर बड़ी आपत्ति हुई थी। ...**(व्यवधान)**... हिन्दुस्तान के नौजवानों को, दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा इस सरकार ने किया था। अब तक करीब साढ़े चार करोड़, पांच करोड़ रोजगार पैदा होने चाहिए थे। ...(समय की घंटी)... सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि सवा करोड़ से ज्यादा रोजगार टूट रहा है। ...**(व्यवधान)**... मजदूर मारे जा रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है। ...**(व्यवधान)**... सरकार कांट्रेक्ट लेबर्स के बारे में सदन को आश्वस्त करे।

SHRI PRADEEP TAMTA (Uttarakhand): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Sharad Yadav.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Sharad Yadav.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Sharad Yadav.

SHRI PARTAP SINGH BAJWA (Punjab): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Sharad Yadav.

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Sharad Yadav.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री आनन्द भास्कर रापोलू (तेलंगाना): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[चौधरी मुनव्वर सलीम]

†**چودھری منور سلیم (اترپردیش):** مہودے، میں بھی مانیئے سدسیئے کے وکتوے سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔

श्री अहमद पटेल (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री दर्शन सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हरिवंश (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के वक्तव्य से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

Need to curb growing religious fundamentalism in the country immediately

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, it is impossible to speak on this subject in three minutes, but I will because it is Zero Hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are capable of doing that.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, regarding religious fundamentalism, what has been happening in the last one week, the last few days, the last one month and the last two years, is a dangerous disturbing situation. If it happens for the first time, we can call it a mistake; if it happens for the second time, we can call it a bigger mistake; if it happens for the third time, we can call it a blunder; but, if it happens and happens and happens, I have to say, Sir, that it is a decision. I believe this is happening not because of a mistake; this is a decision of this Government. Otherwise, Sir, the Defence Minister of the country would not have said what he said yesterday. After the *dalit* suicides, so many of us went and saw that there are people dying because of what happened in different parts of the country. It is not just an aberration. It is the decision of the Government to do this. Sir, for fifteen rupees, people are being killed for buying a biscuit just because they are *dalits*. In Haryana, there are people who are forced to eat cow dung. Sir, let me tell you, I am a *gau-sewak,* we are all *gau-sewaks.* But in the name of *gau-sewak,* don't cross the line. Don't cross the line and become *gau-rakshak,* please. This is the situation which has gone beyond the borders of this country. The Government must be aware of it because this is not a fluke, and, as they are taking these decisions, these are not aberrations. The Government must read as to what the United Nations Human Rights Council's Special Report on Minority Rights had to say about our country. They have said, 'caste-affected discrimination happening in India' with 'minority-like characteristics'. The Government

†Transliteration in Urdu script.